



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 354]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 28, 1972/श्रावण 6, 1894

No. 354]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 28, 1972/SRAVANA 6, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 28th July 1972

S.O. 509(E)/15A/IDRA/72.—Whereas M/s. Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, owning an industrial undertaking, is being wound up under the supervision of the Calcutta High Court and the business of this company is not being continued;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is necessary, in the interests of the general public, and, in particular, in the interests of production of the articles manufactured in the said industrial undertaking, to investigate into the possibility of running or restarting the aforesaid industrial undertaking;

And, whereas, on an application under Section 15A of Industries (Development & Regulation) Act being made by the Central Government to the Calcutta High Court praying for permission to make an investigation into such possibility, the Calcutta High Court has by an order dated the 10th July, 1972, granted the requisite permission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 15A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby appoints, for the purpose of making an investigation into

the possibility of restarting the aforesaid industrial undertaking, a body of persons consisting of:

Chairman

1. Dr. S. P. Verma, Industrial Adviser, Directorate General of Technical Development, Ministry of Industrial Development.

Members

2. Shri A. Bose, Special Officer and Ex-officio Secretary, Sick and Closed Industries Department, Government of West Bengal, Calcutta.
3. Shri S. R. Mallya, Senior Cost Accounts Officer, Ministry of Finance, New Delhi.
4. Shri R. M. Choubey, Deputy Manager (Tech.) Industrial Reconstruction Corporation of India 19, Netaji Subhas Road, Calcutta-1.

2. The above body shall submit its report to the Central Government within a period of six weeks from the date of publication of this Order in the Official Gazette.

3. This Order is in supersession of the Order of the Government of India in the Ministry of Industrial Development No. 76(E)/15/IDRA/72(2), dated the 31st January, 1972.

[No. F. 25(19)/72-CUC.]

K. S. BHATNAGAR, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मंत्रालय

आवेद

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 1972

का० आ० 500(अ)/15ए/आई०डी प्र.र०ए०/72.—यतः मैसर्स कृष्णा सिलिकेट एण्ड ग्लान वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता, जो एक ऐसे उपक्रम का स्वामी है, जिसका, कलकत्ता उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षण के अधीन परिसमापन कर दिया गया है और इस कंपनी का कारबार अब नहीं चल रहा है;

और यतः केन्द्रीय सरकार की राय है कि जन साधारण के हित में, और, विशेषकर, उक्त औद्योगिक उपक्रम में विनिर्मित वस्तुओं के उत्पादन के हित में उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम को चालू रखने या फिर से खलाने की संभावना का अन्वेषण करना आवश्यक है;

और यतः ऐसी संभावना का अन्वेषण करने की अनुज्ञा के लिए प्रार्थना करते हुए केन्द्रीय सरकार द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय को उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, की धारा 15क के अधीन आवेदन दिए जाने पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 10 जुलाई, 1972 के आदेश द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा दे दी है।

अतः अब उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त औद्योगिक उपक्रम को फिर से खलाने की संभावना का अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, एक निकाय नियुक्त करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे—

अध्यक्ष

1. डा० एस० पी० वर्मा,
औद्योगिक सलाहकार,
तकनीकी विकास का महानिदेशालय,
औद्योगिक विकास मंत्रालय।

सदस्य

2. श्री ए० बोरस,
विशेष अधिकारी और पदेन सचिव,
अक्षम और बन्द उद्योग विभाग,
पश्चिमी बंगाल की सरकार,
कलकत्ता ।
3. श्री एस० आर० मलिया,
ज्येष्ठ लागत लेखा अधिकारी,
वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली ।
4. श्री आर० एम० चौबे,
उप प्रबंधक (तकनीक),
भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम,
(इण्डस्ट्रियल रिकन्सट्रक्शन कारपोरेशन ऑफ इण्डिया)
19, नेताजी सुभाष रोड,
कलकत्ता ।

2. उपरोक्त निकाय, राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से छः सप्ताह की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

3. यह आदेश भारत सरकार के औद्योगिक विकास मंत्रालय के आदेश सं० 76(ई०)/15/आई०डी०आर०ए०/72(2), तारीख 31 जनवरी, 1972 को प्रतिष्ठित करता है ।

[सं० फा० 25(19)/72-सी०यू०सी०]

के० एस० भटनागर, संयुक्त सचिव ।

